

**Implementation of JRY**

2041. SHRI GAYA SINGH;

SHRI CHATURANAN  
MISHRA;

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any representation dated 27th March, 1993 regarding prevailing corruption in implementation of Jawahar Rozgar Yojana and distribution of land by the "Pradhan" of village Mir-pur, Tehsil Khair in Janpad Aligairh (Uttar Pradesh) and signed by some members of Gram Panchayat have been received;

(h) if so, the details thereof;

(c) whether any enquiry has been made and action taken thereon; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No. Sir.

(b) to (d) Do not arise.

**Vpplcatons judged with capart**

2052. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that over 7500 applications lodged with Council for Advancement of People's Action and Technology are yet to be screened and processed;

(b) whether such applications will be returned to the applicant's;

(c) the steps being taken to streamline CAPART; and

(d) whether it is also a fact that CAPART has become top-heavy in terms of management?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOP

MENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL); (a) Yes, Sir.

(b) Alter scrutiny applications which not as norms laid down by CAPART be returned to the applicants.

(c) After careful examination suitable steps will be initiated to streamline the functioning of CAPART.

(d) No. Sir,

**जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खोदे गए कुएँ**

**2043. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खोदे गए कुएँ सूख गए हैं :

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) उन कुओं के सूख जाने के क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) जी नहीं ।**

(ख) और (ग) दस लाख कुओं की योजना नामक जवाहर रोजगार की एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों और मुक्त बंधुआ-मजदूरों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुएँ उपलब्ध कराना है 10 लाख कुओं की योजना के अंतर्गत लाभार्थी स्वयं अपने कुओं का निर्माण करते हैं यदि कोई कुओं कम यानी ग़लत खराब पानी ग़लत ग़लत सम्बंधी विफलता के कारण असफल हो जाता है तो कुएँ की खुदाई के लिए किए गए वास्तविक खर्च के प्रतिफल के बराबर मुआवजा दिया जाता है ।